

भ्रष्टाचार सफाई के नाम पर हजारों डकार गए, पंचायत में खुला बड़ा घोटाला

कागजों में बह रही नालियां, जमीन पर सन्नाटा



नवभारत, पनागर। विकासखंड पनागर के अंतर्गत ग्राम पंचायत महगवाँ टगर में कथित भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है, जिसने पंचायत व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पंचायत रिकॉर्ड में जिन नालियों को वर्षों पहले निर्मित बताया गया, वे आज तक जमीन पर मौजूद ही नहीं

हैं। इसके बावजूद साफ-सफाई और निर्माण के नाम पर हजारों रुपये की राशि आहरित कर ली गई। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ग्राम निवासी भोला सिंह राजपूत द्वारा मांगी गई 15 बिंदुओं की जानकारी ने पूरे मामले को परतें खोल दीं। पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी अधूरी, भ्रामक

और संदेहास्पद पाई गई। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए, जबकि प्रस्तुत कागजात में भी हेरफेर की आशंका जताई जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जिन मोहल्लों में आज तक नाली का निर्माण नहीं हुआ, वहां सफाई कार्य का भुगतान किस आधार पर

किया गया। मौके पर न नाली के प्रमाण मिले, न नियमित सफाई के—फिर भी अभिलेखों में कार्य 'पूर्ण' दर्शाया गया है। पुराने वित्तीय अनियमितताओं को छिपाने की कोशिश मामला उजागर होते ही पंचायत में हड़कंप की स्थिति बन गई। बताया

जा रहा है कि वर्ष 2023 में निकाली गई राशि को वर्ष 2026 में कार्य दर्शाकर समायोजित करने के उद्देश्य से जल्दबाजी में काम शुरू कराया गया है। इससे पुराने वित्तीय अनियमितताओं को छिपाने की कोशिश की आशंका बलवती हो रही है। सूत्रों के अनुसार पंचायत के सरपंच रणजीत सिंह ठाकुर, सचिव विनोद तिवारी और सहायक सचिव जितेंद्र काछी की भूमिका जांच के दायरे में है। आरोप है कि उपयंत्री एवं संबंधित तकनीकी अमले को मिलीभगत से कागजों में ही विकास कार्य दर्शाकर भुगतान कराया गया। ग्रामीणों ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष और कठोर जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा पंचायत विकास के बजाय भ्रष्टाचार का केंद्र बनती जाएगी।

इनका कहना है
मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच दल गठित कर दिया गया है। दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।
आयुषी उमाश्याय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पनागर

करोड़ों की इमारतें, लेकिन इलाज नदारद

पड़वार में आरोग्य सेतु योजना बनी 'डॉक्टर विहीन'

नवभारत, मझौली। सरकार की महत्वाकांक्षी आरोग्य सेतु योजना के तहत मझौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पड़वार में अस्पताल भवन तो खड़े कर दिए गए, लेकिन महीनों से डॉक्टरों की नियमित मौजूदगी नहीं होने से ग्रामीणों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। करोड़ों रुपये खर्च कर बनाए गए ये अस्पताल आज सिर्फ ईंट-सीमेंट की शोपीस इमारत बनकर रह गए हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि अस्पतालों में न डॉक्टर मिलते हैं, न नियमित ओपीडी चलती है। गंभीर मरीजों को मजबूरी में निजी अस्पतालों या जिला मुख्यालय का रुख करना पड़ता है। सवाल यह है



कि जब डॉक्टर ही नहीं, तो इन योजनाओं का लाभ आखिर किससे मिल रहा है? अब सबसे बड़ा सवाल सीधे जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) पर उठ रहा है—क्या सीएमएचओ को इन हालात की जानकारी नहीं है? या फिर जानकारी होने के बावजूद जानबूझकर अनदेखी की जा रही है?

हालात नहीं सुधरे तो होगा जनआंदोलन
ग्रामीणों का आरोप है कि यदि

यही स्थिति शहरी क्षेत्र में होती, तो अब तक अधिकारियों की जवाबदेही तय हो चुकी होती। लेकिन ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सेवाओं के साथ हो रहा यह खिलवाड़ सिस्टम की संवेदनहीनता को उजागर करता है। इस मुद्दे पर सामाजिक कार्यकर्ता अजय तिवारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि 'यह सीधी-सीधी जनता के पैसों की बर्बादी और ग्रामीणों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। भवन बनाकर फोटो खिंचवा लेना आसान है, लेकिन डॉक्टरों की तैनाती और निगरानी करना जिम्मेदारों का काम है। यदि जल्द डॉक्टरों की नियमित पदस्थापना नहीं हुई, तो इस लापरवाही के खिलाफ जनआंदोलन किया जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी सीएमएचओ पर तय की जाएगी।

17वें दिन भी नहीं मिला धान का भुगतान

किसानों में आक्रोश, कलेक्टर कार्यालय के घेराव की चेतावनी

नवभारत, मझौली। 'जय जवान... जय किसान' के नारों के बीच मझौली तहसील मुख्यालय के सामने किसानों का धरना 17वें दिन भी जारी है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक न भुगतान हुआ, न कोई ठोस आश्वासन दिया गया है। आलम ये है कि धान खरीदी और तुलाई भुगतान को लेकर श्री जी वेपर हाउस, धनवाही पिपरिया (मझौली) में हुई भारी अनियमितताओं ने किसानों को सड़क पर बैठने के लिए मजबूर



कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान संघ, संयुक्त किसान मोर्चा, करणी सेना परिवार एवं ओबीसी महासभा (म.प्र.) के

संयुक्त समर्थन से चल रहे इस आंदोलन ने अब जिला प्रशासन के लिए सीधी चेतावनी का रूप ले लिया है। किसानों का स्पष्ट कहना है कि भुगतान नहीं हुआ तो

अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। अभी मझौली के किसानों

ने कलेक्टर कार्यालय को घेरने की चेतावनी भी दी है।

तुलाई हुई, उपज उठी, पैसा गायब

किसानों का आरोप है कि 9 फरवरी से जिन किसानों को धान तुलाई स्लाट लगी थी, उनकी उपज जांच के नाम पर तोली ही नहीं गई। जिनकी तुलाई हुई, उनकी उपज पोर्टल पर दर्ज नहीं की गई। वहीं वेयर हाउस परिसर में पड़ी किसानों की उपज बिना सूचना प्रशासन द्वारा उठा ली गई कोई लिखित रसीद या प्रमाण नहीं दिया गया। किसानों का कहना है कि अब न उपज उनके पास है, न भुगतान मिला है—जिससे वे आर्थिक और मानसिक संकट में हैं। विदित हो कि विगत 3 फरवरी से किसान लगातार मझौली तहसील के सामने धरने पर बैठे हैं। 17 दिन बीत जाने के बावजूद—न प्रशासन ने स्थिति की पुष्टि की है, न किसी किसान के खाते में भुगतान पहुंचा है, न जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई हुई है जिससे किसानों में भारी आक्रोश है।

परीक्षा आज से 5वीं-8वीं की बोर्ड जंग, 693 स्टूडेंट्स देंगे एग्जाम

खितौला का यशोदा बाई स्कूल बना जिले का सबसे बड़ा सेंटर

नवभारत, सिहोरा। जिले में आज से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की सबसे बड़ी 'अग्निपरीक्षा' शुरू हो रही है। खितौला बाजार स्थित शासकीय यशोदा बाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को संभवतः इस बार जिले के सबसे बड़े परीक्षा केंद्रों में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ है। यहाँ कक्षा 5वीं और 8वीं के कुल 693 छात्र-छात्राएं एक साथ बैठकर अपना भविष्य लिखेंगे। प्रशासनिक स्तर पर इसे एक बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी के रूप में देखा जा रहा है। परीक्षा ड्यूटी के संबंध में पर्यवेक्षकों की बैठक आयोजित हुई।

9 स्कूलों का एक केंद्र: 5वीं के 342 और 8वीं के 351 छात्र होंगे शामिल इस परीक्षा केंद्र पर केवल स्थानीय नहीं, बल्कि आसपास



की कुल 9 शासकीय और अशासकीय शालाओं के विद्यार्थियों का जमावड़ा लगेगा। आंकड़ों पर नजर डालें तो कक्षा

5वीं के 342 और कक्षा 8वीं के 351 परीक्षार्थी इस केंद्र से परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा विभाग ने इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए बैठक व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए हैं।

नो स्ट्रेस जोन: स्नेहपूर्ण व्यवहार से दूर होगा बच्चों का डर

जनशिक्षा केंद्र प्रभारी दीप्ति सिंह बैस ने पर्यवेक्षकों को कड़े लहजे में निर्देश दिए हैं कि परीक्षा केंद्र का माहौल तनावपूर्ण नहीं, बल्कि खुशनुमा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों के मन में बोर्ड परीक्षा का डर होता है, इसलिए शिक्षकों को उनके साथ 'स्नेहपूर्ण' व्यवहार करना होगा। लक्ष्य स्पष्ट है—नकल विहीन और भयमुक्त वातावरण।

सहयोगी टीम तैयार
परीक्षा के सफल संचालन के

लिए एक मजबूत टीम तैनात की गई है। इस दौरान जनशिक्षक श्याम राव मांडलेकर, अहसान इस्लाम, अरविन्द तिवारी, नरेश पटेल, बलराम बर्मन और योगेन्द्र मिश्रा सहित कई वरिष्ठ

शिक्षक मॉनिटरिंग की भूमिका में रहेंगे। विद्यालय प्रबंधन ने दावा किया है कि परीक्षार्थियों के लिए पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है।

राज्य शिक्षा केंद्र के नियमों का होगा पालन

परीक्षा की शुचित्ता बनाए रखने के लिए जनशिक्षा केंद्र स्तर पर हुई बैठक में पर्यवेक्षकों को उनकी जिम्मेदारियां सौंपी गईं। केंद्राध्यक्ष प्रमोद नामदेव और सहायक केंद्राध्यक्ष महेंद्र त्रिपाठी ने स्पष्ट किया कि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी गाइडलाइन में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ड्यूटी में तैनात हर शिक्षक की जवाबदेही तय कर दी गई है।

रिपोर्टिंग टाइम का सख्त पहरा: 1 घंटे पहले आना अनिवार्य

बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों की मौजूदगी के कारण केंद्र पर किसी भी प्रकार की अफरा-तफरी न हो, इसके लिए समय प्रबंधन का खास प्लान बनाया गया है। सभी संबंधित स्कूलों के शिक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने छात्र-छात्राओं को निर्धारित समय से ठीक 1 घंटा पहले केंद्र पर पहुंचाना सुनिश्चित करें, ताकि रोल नंबर सच करने और बैठने में समय बर्बाद न हो।